where already the sugar industry exists in a big way. To avoid one-sided licensing in the Sugar Industry, there is a need to consider all aspects of inter-State priorities for balanced regional development and to ensure that the backward areas of the country also get a fair deal and at least an opportunity to claim a share of new sugar projects licensed in any sugar year. A decision is under active consideration.

एन०बी०सी०सी०के चेयरमैन के दौरों से सम्बन्धित नियम

3161. **श्री बाबू राव परांजपे** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड ने अधिकारियों के देश और विदेशों के दौरे करने के लिए कुछ नियम बनाये थे ; और

(ख) यदि हां, तो क्या वर्तमान चेयरमैन ने नियमानुसार दौरे किए हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो देश और विदेशों में उनके द्वारा किए गए दौरों का ब्योरा क्या है और उन पर कितना खर्च हुआ था। वर्ष 1982, 1983 और 1984 के दौरान इनकी क्या उपलब्धियां रहीं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री(श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

तिलहनों का उत्पादन

3162. **श्री के० ए० स्वामी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान देश में वर्ष-वार तिलहनों का कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) क्या यह देश की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त था या आवश्यकता से कम था ;

(ग) यदि कम था, तो कमी को किस प्रकार पूरा किया गया ; और

(घ) तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने और इस मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) देश में फसल वर्ष 1982-83 के दौरान तिलहनों का कुल उत्पादन 105.5 लाख मीटरी टन था। फसल वर्ष 1983-84 के लिए, इस समय अनुमान लगाया जाता है कि उत्पादन 126.85 लाख मीटरी टन के लगभग होगा।

(ख) और (ग) इस समय खाद्य तेलों का देशी उत्पादन देश की घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। खाद्य तेलों की मांग और आपूर्ति का अन्तर आयात से पूरा किया जाता है।

(घ) 1983-84 तक चल रही तिलहनों के विकास के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं को नया रूप दिया गया है और उन्हें एक ठोस राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना में मिला दिया गया है, जिसे देश में 1984-85 में तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है, जिस पर भारत सरकार को शत-प्रतिशत सहायता से 38 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है। इस परियोजना के अन्तर्गत मूंगफली, तोरिया व सरसों, सोयाबीन और सूरजमुखी के बारे में विशेष कार्यक्रम तथा मूंगफली, तोरिया व सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, कुसुम, रामतिल और तिल सम्बन्धी सघन तिलहन विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के अलावा, तिलहनों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए अनुसंधान प्रयासों में तेजी लाई जा रही है। उत्पादकों को उपयुक्त मूल्य-नीतियों के माध्यम से अच्छे प्रोत्साहन प्रदान किए जा रहे हैं। इसके अलावा केरल और अण्डमान व निकोबार द्वीप

समूह ग्रेड आयल पाम की खेती शुरू की गई है। इसके अतिरिक्त वृक्ष और वन मूलक तिलहनों, चावल की भूसी आदि के उपयोग में भी तेजी लाई जा रही है।

Allotment of Land by D.D.A. to the Co-operative House Building Societies

3163. SHRI RAM AWADH : Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state :

(a) the number of the co-operative house building societies registered with Delhi Development Authority so far ;

(b) their order of priority with regard to allotment of land to them ; and

(c) the approximate time by which each of these societies will be allotted land, complete details thereof ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF SPORTS, IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN) : (a) to (c). DDA last invited applications for allotment of land from Co-operative group housing societies in July-August, 1981. Against this 453 Co-operative group housing societies registered with the DDA for allotment of land. Out of these DDA have made allotment of land to all the eligible 424 societies during the years 1982 and 1983.

गांधी नगर में राष्ट्रीय खेल संस्थान का पश्चिमी जोनल केन्द्र खोला जाना

3164. श्री मोती भाई आर० चौधरी : क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने गांधी नगर में राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला का पश्चिमी जोनल केन्द्र खोलने के लिये कोई अनुरोध किया है और यदि हां, तो उक्त अनुरोध कब किया गया था और उसे कब तक स्वीकार कर लिया जायेगा ;

(ख) गांधी नगर में खेलों का जोनल केन्द्र खोलने के लिये सभी अपेक्षित सुविधायें उपलब्ध होने के बावजूद, इस अनुरोध को स्वीकार करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या गुजरात राज्य खेल के मामले में पीछे रह रहा है और यदि हां, तो क्या राज्य में खेलों को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस केन्द्र को शीघ्र ही खोल दिया जाएगा ?

खेल विभाग में उप मंत्री(श्री अशोक गहलोत,: (क) और (ख) जी, हां। गुजरात सरकार ने सितम्बर, 1983 में नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान का गांधी नगर में पश्चिमी केन्द्र स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इसी प्रकार का एक प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकार से भी प्राप्त हुआ है। तदनुसार, ने०सु०रा०खेल संस्थान के पश्चिमी केन्द्र की स्थापना को सातवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे में शामिल किया गया है। तथापि, मामले में अन्तिम निर्णय केवल सातवीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद ही सम्भव होगा।

(ग) खेलों के मामले में विभिन्न राज्यों से सम्बन्धित स्तर को निश्चित करने के लिए कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

Payment of Compensation to Oberois for land Acquired by Government

3165. SHRI H.N. NANJE GOWDA : Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state :

(a) whether a number of plots of land belonging to the Oberoi Hotels Ltd. in Nehru Place were acquired by Government and no compensation has been paid to them so far ;

(b) if so, full facts of the land owned by the Oberois in Nehru Place ;

(c) when the same was acquired by Government ; and

(d) when and on what basis, compensation is proposed to be paid ?